निरीक्षण प्रबन्धों को कड़ा कर करें, उचित दर दुकानों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए सलाहकार/सतर्कता समितियां गठित करें आदि । समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से राज-सहायता युक्त खाद्यान्न सप्लाई करने की एक योजना पहले से ही चल रही है । तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है ।

(ख) देश में 3.5 लाख से अधिक उचित दर की दुकानें हैं । राजस्थान में इनकी संख्या 14647 है, जो लगभग 3.4 करोड़ आबादी की सेवा कर रही है ।

Ticketless passengers

2298. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the number of ticketless rail travellers in the country is increasing manifold since the present Government have taken over;

(b) whether the machinery to detect the ticketless rail travellers has also failed to detect such cases in the trains; and

(c) if so, what other steps Government propose to take to stop ticketless rail travelling in the country?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Miraj-Bangalore Railway Line

2299. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether conversion of Miraj-Bangalore Railway line will be taken up during Eighth Plan; and

(b) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Specific Gauge Conversion proposals to be taken up during the Eighth Plan have not been identified;

(b) Does not arise.

असिंचित भूमि से कृषि उत्पादन

2300. **सरदार हरजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल कृषि भूमि का 70 प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस भूमि से कृषि उत्पादन देश की सिंचित भूमि के कृषि उत्पादन के आधे से भी कम है ;

(ग) क्या सरकार ने इस भूमि से होने वाले प्रति हैक्टेयर उत्पादन का अनुमान लगाया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार की भूमि से उत्पादन दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; और

(ङ) ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रम की रूप रेखा क्या है?

उप प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) 1986-87 (नवीनतम उपलब्ध) के भू-उपयोग सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर देश में कुल अ-सिंचित क्षेत्र लगभग 69 प्रतिशत है ।

(ख) सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन का अलग से अनुमान नहीं लगाया जाता ।

(ग) से (ङ) प्रमुख राज्यों द्वारा असिंचित क्षेत्रों के लिए प्रति हैक्टेयर

अनुमानित उत्पादकता आंकी गई है । अनुसिवित क्षेत्रों में चुनिंदा फसलों की हैक्टेयर राज्यवार पैदावार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 153, अनुपत्र संख्या –99]

1986–87 से 16 राज्यों में वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । इस कार्यक्रम में मृदा एवं नमी प्रबंध, आकस्मिक बीज भण्डारण और पौद तथा घास के बीज/कलमों की सप्लाई किसानों और फील्ड कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन, फील्ड परीक्षण करना, उन्नत औजारों और उपकरणों का उपयोग आदि शामिल हैं । इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते ।

Sealing of basement of a five star hotel on Ring Road

2301. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the DDA has sealed the basement of a five star hotel on ring road near R. K. Puram which approved for parking but was illegally being used as a night club by the hotel;

(b) if so, whether Government propose to take any action against the owner of the hotel who has illegally used the basement in the hotel; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The Delhi Development Authority has reported that the use of the parking space on the Upper basement of Hyatt Regency Hotel as a restaurant coming to its notice, order for sealing under Section 31-A of the Delhi Development Act, 1957 was passed on the 2nd March, 1990 and the premises used as restaurant were sealed on the 3rd March, 1990. This order was challenged in the High Court, which has remanded the case to the D.D.A. for disposal in accordance with the directions of the Court.

Waiting list for Lodhi Colony and Sarojini Nagar Government Quarters

2302. SHRI N. RAJANGAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of the aspirants of type 'C' accommodation at Lodhi Colony and Sarojini Nagar together with the dates since when they are awaiting

(b) by when they are likely to be allotted accommodation at the said places; and

(c) the number of Government servants who have been allotted Type 'C' accommodation at Lodhi Colony, on out of turn basis and under which rules?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) As per change waiting list maintained for Lodhi Colony and Sarojini Nagar in respect of Type-C accommodation, the details of waiting are given below:—

Lodhi Colony	
In-turn - 2105 employees	Since October, 1986
Ad-hoc - 146 employees	
Sarojin Nagar	
In-turn - 374 employees	Since June, 1989
Ad-hoc - 4 employees	